सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 29 अगस्त, 2020

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 29.07.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने और कंटेनमेंट जोनों में, लॉकडाउन को 30.09.2020 तक बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी करने का निदेश दिया है;

अत: अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि **अनलॉक-4** के बारे में **संलग्न दिशानिर्देश**, 30.09.2020 तक लागू रहेंगे।

हस्ता0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के बारे में दिशानिर्देश (अनलॉक 4)

[गृह मंत्रालय के दिनांक 29, अगस्त, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के अनुसार]

1. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में अनलॉक 4 के दौरान अनुमति प्रदान की गई गतिविधियां

कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में, निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी:

(i) छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए, स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, 30 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे। तथापि, निम्नलिखित की अनुमति होगी:

क. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

ख. राज्य /संघ राज्य क्षेत्र 21 सितम्बर, 2020 से कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में ऑनलाइन टीचिंग/टेली काउंसलिंग तथा संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में एक समय में 50 प्रतिशत तक शैक्षणिक और गैर- शैक्षणिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं जिसके बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

ग. केवल कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वेच्छा से अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति अपेक्षित होगी तथा इसकी अनुमति 21 सितम्बर, 2020 से दी जाएगी जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

घ. कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या राज्य सरकारों के पास पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), शॉटटर्म ट्रेनिंग सेंटरों में दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) तथा उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति प्राप्त होगी।

इनको 21 सितम्बर, 2020 से अनुमति प्रदान की जाएगी जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

ड. केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएच. डी.) तथा टैक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्रामों, जिनके लिए लेबोट्री/प्रायोगिक कार्य अपेक्षित होते हैं, से पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान । इनको अनुमति, स्थिति के आकलन के आधार पर तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के परामर्श से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ii) मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति, गृह मंत्रालय के परामर्श से, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा 7 सितम्बर, 2020 से क्रमबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

(iii) सामाजिक/शैक्षिणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यों तथा अन्य सम्मेलनों में, 100 लोगों की सीमा के साथ, 21 सितम्बर, 2020 से अनुमति दी जाएगी तथा इसके लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने अथवा सैनिटाइजर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

तथापि, अधिकतम 50 अतिथियों की सीमा के साथ, विवाह समारोह तथा अधिकतम 20 लोगों की सीमा के साथ, अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी, इसके बाद इनमें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

(iv) सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। तथापि, ओपन एयर थिएटरों को 21 सितम्बर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

(v) यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय।

2. कोविड-19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-I** में यथाविर्निष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोनों तक सीमित रखना

(i) कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा।

(ii) कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण, संक्रमण की श्रृंखला को कारगर तरीके से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा माइक्रो लेवल पर किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में कंटेनमेंट के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में लोगों के आने और इन जोनों से लोगों के बाहर जाने को रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। इन कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी, और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

(iii) सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोनों की सूचना दी जाएगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सूचना साझा की जाएगी।

4. केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कंटेनमेंट जोनों से बाहर कोई लोकल लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर स्तर पर) नहीं लगाएंगी।

5. राज्य के भीतर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं

राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन /ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

6. मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ लोगों की आवाजाही

यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन; घरेलू यात्री हवाई यात्रा; वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स में लोगों का आवागमन; तथा इंडियन सीफेयरर्स का साइन-ऑन और साइन-ऑफ जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

7. कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

8. आरोग्य सेतु का उपयोग

(i) आरोग्य सेतु, संक्रमण के आशंकित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

(ii) कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।

(iii) जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी

9. दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगी।

ii. सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।

iii. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।

10. दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू, अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

हस्ता0/-
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

अनुलग्नक-।

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है।

2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

3. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना**, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. **घर से कार्य करना (डब्ल्यूएफएच):** जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

5. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।

6. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

7. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।

8. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

*****

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसेअपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

क. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

ख. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा.— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।

*****